

जे.डी.ए. के तत्कालीन सचिव सहित अन्य के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर, प्रथम ने जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश की अनदेखी व फर्जीवाड़ा करने से जुड़े मामले में जेडीए के तत्कालीन सचिव उज्ज्वल राठौड़, मुख्य प्रवर्तन अधिकारी रघुवीर सैनी, जोन 9 प्रवर्तन नियंत्रक धर्मसिंह व उप प्रवर्तन नियंत्रक राजेश शर्मा के खिलाफ गांधी नगर पुलिस थाने को एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने यह आदेश एचएस अडवानी के परिवाद पर दिए।

अदालत ने माना कि प्रथम दृष्टया आरोपियों ने जेडीए अपीलीय अधिकरण के आदेश की अवहेलना कर नए सिरे से दुर्गा कुमारी के अतिक्रमण को वैध घोषित करने के लिए कार्यालय टिप्पणियां तैयार कीं। इससे परिवादी के अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

परिवाद में कहा कि उसे रेलवे मेन्स हाउसिंग को-ऑपरेटिव सोसायटी की आनन्द विहार योजना में भूखंड संख्या-14 का पट्टा 19 जुन 1994 को जारी किया था। वहीं उसकी खतेदारी से बाकी रही 2 बीघा 7 बिस्वा जमीन को 0.83 हेक्टेयर बताते हुए दुर्गादेवी ने पट्टा

अतिरिक्त मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट क्रम-2 महानगर, प्रथम ने जेडीए ट्रिब्यूनल के आदेश की अनदेखी व फर्जीवाड़ा करने से जुड़े मामले में आदेश दिये

मांगा। जबकि उसे 0.59 हेक्टेयर जमीन का ही पट्टा मिल सकता था,

लेकिन दुर्गाकुमारी को गलत तरीके से पट्टा जारी करने का आदेश हो गया।

72 घंटे पहले नोटिस दिए बिना होटल बिल्डिंग पर नहीं करें कार्रवाई : हाईकोर्ट

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिए हैं कि दिल्ली रोड पर स्थित कान्हा होटल पर कार्रवाई से 72 घंटे पहले नोटिस दिए बिना उसकी बिल्डिंग पर कोई कार्रवाई नहीं करे। जस्टिस अशोक जैन की अवकाशकालीन एकलपीठ ने यह आदेश कान्हा होटल के ओर से दायर याचिका में पेश प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि इस मामले में विस्तृत सुनवाई की जरूरत है। ऐसे में यह

उचित नहीं है कि अवकाशकालीन कोर्ट प्रकरण के किसी पहलू पर विचार करे। अदालत ने कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के आधार पर होटल की बिल्डिंग को तोड़ने की आशंका मात्र पर यह प्रार्थना पत्र दायर किया गया है।

केन्द्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल आरडी रस्तोगी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने वर्ष 2018 से वर्ष 2022 तक कूकस के पास पांच सितारा

इसके खिलाफ परिवाद ने जेडीए में शिकायत की, लेकिन उसकी शिकायत के बाद भी अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

वहीं जेडीए के अफसरों ने मिलीभगत कर एक फर्जी रिपोर्ट बनाई जिसमें अतिक्रमण नहीं होना बताया

इसके खिलाफ परिवाद दायर कर जेडीए के तत्कालीन अफसरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

उपमुख्यमंत्री से वार्ता के बाद परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल समाप्त



उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से शुक्रवार को परिवहन निरीक्षक संघ ने मुलाकात की।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से शुक्रवार को मुलाकात के बाद परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हुई। जिसके बाद सोमवार से परिवहन निरीक्षक काम पर लौट सकेंगे।

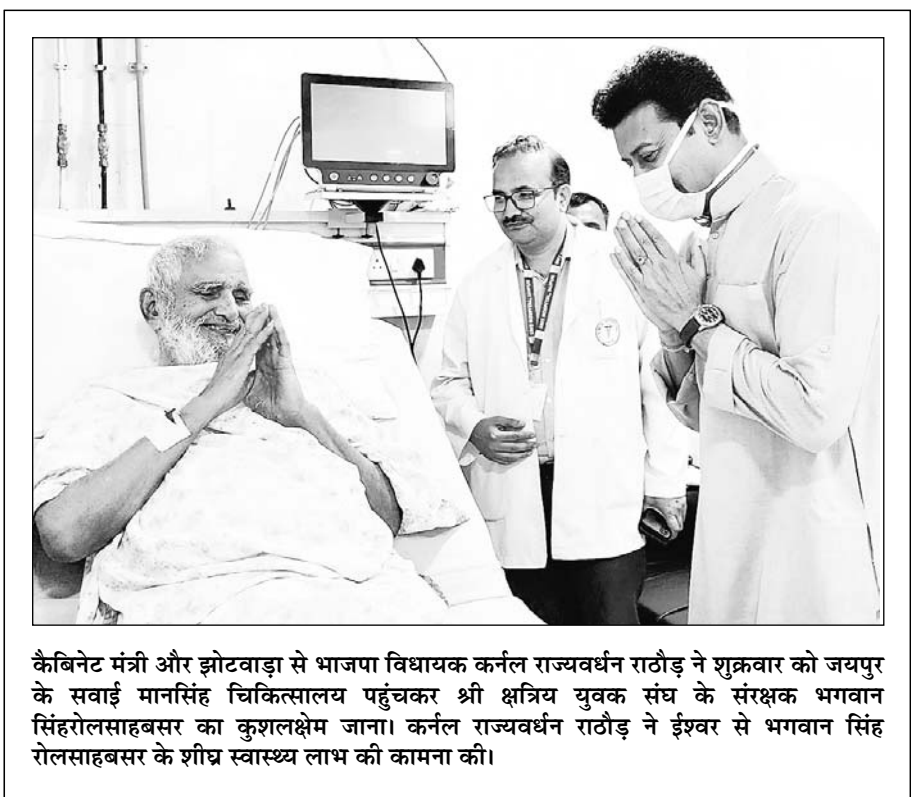
डॉ. बैरवा ने अपने निवास पर परिवहन निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वार्ता की जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि

राज्य सरकार प्रदेश के हर एक कर्मचारी के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उच्च मनोबल के साथ प्रदेश हित में कार्य करें। उन्होंने परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट मामले में सख्त स्तर पर वार्ता कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आवासन दिया ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों से विभाग में निरीक्षकों

की उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसरों की मांग पर भी सकारात्मक चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर उचित कार्यवाही करने का आवासन दिया। परिवहन निरीक्षक संघ ने उपमुख्यमंत्री की इस पहल और उनके सकारात्मक रुख के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया।

इस मौके पर राजस्थान परिवहन संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी, महासचिव अनिल बसवाल सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।



कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से भाजपा विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने शुक्रवार को जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय पहुंचकर श्री कृष्णिय युवक संघ के संरक्षक भगवान सिंहरोलसाहबसर का कुशलखण्ड जाना। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने ईश्वर से भगवान सिंह रोलसाहबसर के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।

राजस्थान सहित तीन राज्यों के एन.आई.ए. के छापे

जयपुर। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआई) ने मानव तस्करी और साइबर क्राइम मामले में शुक्रवार को राजस्थान सहित



तीये की बैठक

हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती पुष्पा शर्मा

पति स्व. श्री आर. बी. एल. शर्मा (गायत्री परिवार) का स्वर्गवास 27.06.2024 को हो गया। तीये की बैठक 29.06.2024 को सायं 5 से 6 बजे श्री कृष्णा मन्दिर, 20-दुकान, आदर्श नगर, में होगी।

शोकाकुल : दिनेश शर्मा (SBI) निशा, हरीश शर्मा (SBBJ) अर्चना, अशोक शर्मा (XEn RVUNL) शीतू (पुत्र-पुत्रवधु), अनन्त-किरण, लीलाश्री-पुजा (पौत्र-पौत्रवधु), निकिता -प्रखर, यज्ञा-सिद्धार्थ, (पौत्री-दामाद), अनुश्री(पौत्री)



हमारी पूजनीय माताजी श्रीमती भगवती देवी जी

धर्मपत्नी स्व. श्री रघुनाथ जी खगमाल का स्वर्गवास 27.06.2024 को हो गया। तीये की बैठक 29.06.2024 (शनिवार) को सायं 5:30 से 6:30 बजे आदर्श विद्या मंदिर, गेट न.2, अंबाबाडी बसके के पास, जयपुर पर होगी।

शोकाकुल- उमाशंकर- शारदा (पुत्र-पुत्रवधु), मनीष कुतिका, शुभम- कल्पना (पौत्र-पौत्रवधु), दिव्या- राहुल जी (पौत्री-दामाद), प्रायुष (पडपौत्र), सुशाविका (पडपौत्री), रिधान (पड-दोहिता), लक्ष्मण, प्रेमचंद, राजाबाबू, इंद्रसिंह, राजकिशोर, रवि (भतीजे) एवं समस्त खगमाल परिवार। मो. 9460434361, 7665117173, 7062702541

नम्बर मिलाइए 9587884433

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक कराये।

विधानसभा सत्र को लेकर कंट्रोल रूम की स्थापना

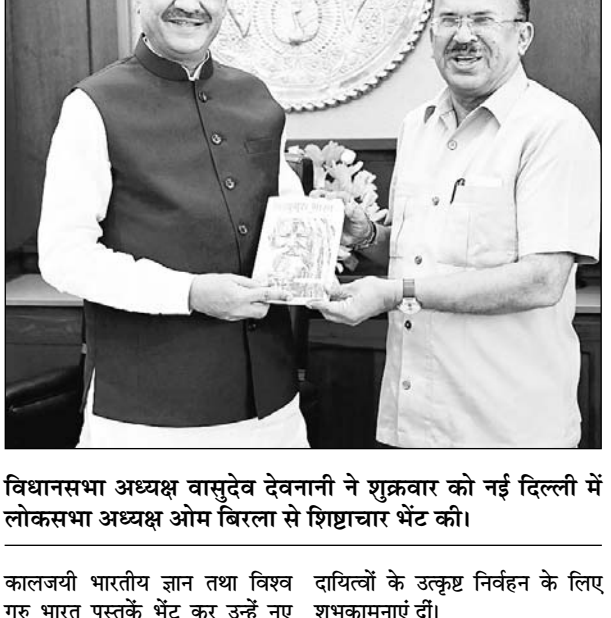
जयपुर। विधानसभा के सत्र की बैठक 3 जुलाई से प्रारम्भ होगी। सत्र में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों के जवाब सही समय पर भिजवाने के लिए कलकट्टे में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। कलकट्टे प्रकाश राजपुरोहित ने बताया कि कंट्रोल रूम कार्यदिवस के अतिरिक्त राजकीय अवकाश के दिनों में भी सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक दो परियों में संचालित किया जाएगा।

राजस्थान आवासन मण्डल ने बेसिक रेंट्स तय किये

जयपुर। राजस्थान आवासन मंडल की ओर से प्रदेशभर में किए जाने वाले सभी कार्यों के लिए एकीकृत बेसिक शेड्यूल ऑफ रेंट्स यानी -2024 तय कर दी गई है। इस -2024 का विमोचन राजस्थान आवासन मंडल के अध्यक्ष टी. रविकांत के द्वारा किया गया। अब तक राजस्थान आवासन

स्पीकर वासुदेव देवनानी की लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात

जयपुर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित केन्द्रीय मंत्रियों से शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने सभी को उनके नए कार्यभार के लिए शुभकामनाएं दीं। देवनानी लोकसभा अध्यक्षओम बिरला से संसद भवन में मिले। वहां उन्होंने बिरला को गुलदस्ता भेंट करते हुए लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष बनने पर बधाई दी। देवनानी ने कहा है कि बिरला का लोकसभा में लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनने पर राजस्थान प्रदेशवासियों का मान और गौरव बढ़ा है। पूरे देश में राजस्थान प्रदेश के लिये यह सम्मानजनक है।



विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने शुक्रवार को नई दिल्ली में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की।

एल.आई.सी. ने उपभोक्ताओं को किया आगाह

जयपुर, (का.सं.)। भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से प्रेस विज्ञापित जारी कर कहा गया कि कुछ समाचार लेखों और अन्य प्रकाशनों के अनुसार जो कुछ संस्थाओं द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) के मौजूदा पॉलिसीधारकों द्वारा रखी गई पॉलिसियों को एलआईसी को सौंपने के विकल्प के रूप में (बिक्री/हस्तांतरण, असाइनमेंट या अन्यथा) अधिग्रहित करने की पेशकश करने वाले उत्पाद/सेवाओं से संबंधित है। एलआईसी ऐसी किसी भी संस्था या ऐसी संस्थाओं द्वारा पेश किए जा रहे

उपभोक्ताओं को किया आगाह

उत्पादों और/या सेवाओं से संबद्ध नहीं है, और एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त हित है कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।

आम सूचना - सूचित किया जाता है कि वे अधिनियम 1938 के अंतर्गत एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त हित है कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।

आम सूचना - सूचित किया जाता है कि वे अधिनियम 1938 के अंतर्गत एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

प्रभावशाली ऐग्री वैल्यू चैन फाइनेंसिंग के लिए सहयोगी डिजिटल प्रणालियों का विकास करें : मनोज आहूजा

जयपुर। उपमुख्यमंत्री व परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा से शुक्रवार को मुलाकात के बाद परिवहन निरीक्षक संघ की हड़ताल खत्म हुई। जिसके बाद सोमवार से परिवहन निरीक्षक काम पर लौट सकेंगे।

डॉ. बैरवा ने अपने निवास पर परिवहन निरीक्षक संघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर वार्ता की जिसके परिणामस्वरूप निरीक्षक संघ ने हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया। उपमुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि

राज्य सरकार प्रदेश के हर एक कर्मचारी के हितों के प्रति संवेदनशील है। उन्होंने कहा कि विभाग के समस्त अधिकारी कर्मचारी उच्च मनोबल के साथ प्रदेश हित में कार्य करें। उन्होंने परिवहन निरीक्षक के साथ मारपीट मामले में सख्त स्तर पर वार्ता कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही का आवासन दिया ताकि भविष्य में इस तरह के कृत्यों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।

उपमुख्यमंत्री ने संगठन के पदाधिकारियों से विभाग में निरीक्षकों की उच्च पदों पर पदोन्नति के अवसरों की मांग पर भी सकारात्मक चर्चा की। उपमुख्यमंत्री ने सभी मांगों पर उचित कार्यवाही करने का आवासन दिया। परिवहन निरीक्षक संघ ने उपमुख्यमंत्री की इस पहल और उनके सकारात्मक रुख के प्रति विश्वास व्यक्त करते हुए उनका आभार जताया।

इस मौके पर राजस्थान परिवहन संघ के अध्यक्ष राजेश चौधरी, महासचिव अनिल बसवाल सहित संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

उत्पादों और/या सेवाओं से संबद्ध नहीं है, और एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त हित है कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।

आम सूचना - सूचित किया जाता है कि वे अधिनियम 1938 के अंतर्गत एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त हित है कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।

आम सूचना - सूचित किया जाता है कि वे अधिनियम 1938 के अंतर्गत एलआईसी के पूर्व कर्मचारियों/कार्मिकों द्वारा दिए गए कोई भी कथन ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तिगत हैं। हम इसके संबंध में किसी भी जिम्मेदारी या दायित्व से इनकार करते हैं।

एलआईसी पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट को बीमा अधिनियम, 1938, जिसमें इसकी धारा 38 भी शामिल है, के अनुसार किया जाना चाहिए। लागू कानूनों के तहत, पॉलिसियों को किसी भी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट पर

कार्रवाई करने से इनकार कर सकती है, जहाँ के पास यह मानने के लिए पर्याप्त हित है कि ऐसी बिक्री/हस्तांतरण या असाइनमेंट वास्तविक नहीं है या पॉलिसीधारक के हित में नहीं है या सार्वजनिक हित में है या बीमा पॉलिसी के व्यापार के उद्देश्य से है। हम सभी पॉलिसीधारकों से आग्रह करते हैं कि वे अपनी पॉलिसी पर कोई भी निर्णय लेने से पहले पूरी सावधानी बरतें, जो उनकी वित्तीय सुरक्षा और उनके परिवार के लिए जोखिम कवर को खतरे में डाल सकता है। किसी भी प्रस्ताव का जवाब देने से पहले, कृपया हमारी शाखाओं में हमारे किसी भी अधिकारी से परामर्श करें।